GK/GS का

महा संग्राम

POLITY

केंद्र - राज्य संबंध
(CENTRE - STATE RELATION)

हमारे TOPIC EXPERT के साथ

देखें शाम 07:00 बजे

LIVE

BY GS GURU

केंद्र-राज्य संबंध

Centre-State Relations

- The Indian Constitution's federal system divides all legislative, executive, and financial powers between the Center and the States.
- However, because the Constitution established a unified judicial system to uphold both federal and state laws, there is no division of powers in the judiciary.
- भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच सभी विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को विभाजित करती है।
- हालाँकि, क्योंकि संविधान ने संघीय और राज्य दोनों कानूनों को बनाए रखने के लिए एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है, न्यायपालिका में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है।

- Even though the federal government and the states are leaders in their own fields, for the federal system to work effectively, there must be the greatest possible concord and cooperation between them.
- भले ही संघीय सरकार और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं, संघीय प्रणाली को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, उनके बीच सबसे बड़ा संभव सद्भाव और सहयोग होना चाहिए।

- All legislative, executive and financial powers are divided between the centre and the states according to the Indian constitution in the context of Centre-State Relations.
- There are three types of relationships involved in the centre - states relations:
  - Legislative Relations
  - Administrative Relations
  - Financial Relations
- केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसार सभी विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं।
- केंद्र-राज्य संबंधों में तीन प्रकार के संबंध शामिल होते हैं:
  - विधायी संबंध
  - प्रशासनिक संबंध
  - वित्तीय संबंध

Legislative Relations

- Article 245 to 255 of the constitution deals with the legislative relation between the centre and states. Indian constitution also divides the legislative power between the centre and states with respect to both territories and the subjects of legislation.

विधायी संबंध

- संविधान का अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान दोनों क्षेत्रों और कानून के विषयों के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति को भी विभाजित करता है।

Administrative Relations

- The distribution of legislative authority has resulted in a shared executive branch between the federal government and the states.
- Article 256 to 263 of the constitution deals with the administrative relation between the Centre and States.

प्रशासनिक संबंध

- विधायी प्राधिकार के वितरण के परिणामस्वरूप संघीय सरकार और राज्यों के बीच एक साझा कार्यकारी शाखा बन गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध से संबंधित है।

Financial Relations

- Article 268 to 293 of the constitution deals with Centre-State Financial Relations.

वित्तीय संबंध

- संविधान का अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है।

Important Recommandations on Centre-State Relations

Administrative Reforms Commission

- The creation of an interstate council under Article 263 of the constitution
- Appointment of governors with substantial expertise in public service and impartial viewpoints
- The most power has been granted to states.

केंद्र-राज्य संबंधों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें

प्रशासनिक सुधार आयोग

- संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण
- सार्वजनिक सेवा में पर्याप्त विशेषज्ञता और निष्पक्ष दृष्टिकोण वाले राज्यपालों की नियुक्ति
- सबसे अधिक शक्ति राज्यों को दी गई है

Administrative Reforms Commission

- In order to reduce the state's reliance on the federal government, more financial resources ought to be distributed to them.
- Federal armed troops are stationed in states at their request or on their own initiative.

प्रशासनिक सुधार आयोग

- संघीय सरकार पर राज्य की निर्भरता को कम करने के लिए, उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन वितरित किए जाने चाहिए।
- संघीय सशस्त्र सैनिक राज्यों में उनके अनुरोध पर या उनकी स्वयं की पहल पर तैनात किए जाते हैं।

Sarkaria Commission Recommendations

- Setting up a permanent inter-State Council under Article 263
- Article 356 should only be utilized when necessary.
- The all-India service institution needs to be strengthened.
- The residuary power of taxation should belong to the parliament.
- The states should be informed of the President's grounds for his or her vetoes of state legislation.

सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशें

- अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना
- अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए।
- अखिल भारतीय सेवा संस्थान को मजबूत करने की जरूरत है.
- कराधान की अवशिष्ट शक्ति संसद की होनी चाहिए।
- राज्यों को राज्य विधान पर वीटो के लिए राष्ट्रपति के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

Sarkaria Commission Recommendations

- Without the consent of the states, the Center ought to be able to use its military forces. However, it would be ideal if the states were consulted.
- The centre should consult the states before making law on the subject of concurrent list.
- Governors should be allowed to complete their five-year terms.
- The position of Linguistic Minority Commissioner should be filled.

सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशें

- राज्यों की सहमति के बिना, केंद्र को अपने सैन्य बलों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हालाँकि, यह आदर्श होगा यदि राज्यों से परामर्श किया जाए।
- समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
- राज्यपालों को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का पद भरा जाए।

Punchhi Commission Recommendations

- The impeachment process is used to remove governors after a five-year tenure.
- The Union should exercise extreme prudence when asserting Parliamentary precedence in matters given to the states.
- It specified the number of criteria to be taken into account when choosing governors.

पुंछी आयोग की सिफ़ारिशें

- महाभियोग प्रक्रिया का उपयोग पांच साल के कार्यकाल के बाद राज्यपालों को हटाने के लिए किया जाता है।
- राज्यों को दिए गए मामलों में संसदीय प्राथमिकता का दावा करते समय संघ को अत्यधिक विवेकशीलता बरतनी चाहिए।
- इसने राज्यपालों को चुनते समय ध्यान में रखे जाने वाले मानदंडों की संख्या निर्दिष्ट की।

Punchhi Commission Recommendations

- The term limit for the government should be set at five years.
- Governors could be subject to the same impeachment process as the president.

पुंछी आयोग की सिफ़ारिशें

- सरकार की कार्यकाल सीमा पांच वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए।
- राज्यपालों पर राष्ट्रपति के समान ही महाभियोग प्रक्रिया चल सकती है।

Q. 1 The state of Telangana was officially formed in ________.

तेलंगाना राज्य का आधिकारिक तौर पर गठन ________ में हुआ था।

20

(a) 2016

(b) 2015

(c) 2014

(d) 2011

Q.2 The states of Maharashtra and Gujarat were created in _____.

महाराष्ट्र और गुजरात राज्य _____ में बनाए गए थे।

(a) 1962

(b) 1959

(c) 1961

(d) 1960

States	Founded Year
Andhra Pradesh	1. Nov. 1956
Arunachal Pradesh	20. Feb. 1987
Assam	26. Jan. 1950
Bihar	22 March 1912
Chhattisgarh	1. Nov. 2000
Goa	30. May. 1987
Gujarat	1. May. 1960
Haryana	1. Nov. 1966
Himachal Pradesh	25. Jan. 1971
Jharkhand	15. Nov. 2000
Karnataka	1. Nov. 1956
Kerala	1. Nov. 1956

Madhya Pradesh	1. Nov. 1956
Maharashtra	1. May. 1960
Manipur	21. Jan. 1972
Meghalaya	21. Jan. 1972
Mizoram	20. Feb. 1987
Nagaland	1. Dec. 1963
Odisha	26. Jan. 1936
Punjab	1. Nov. 1956
Rajasthan	1. Nov. 1956
Sikkim	16. May. 1975
Tamil Nadu	1 Nov 1956
Telangana	2. Jun. 2014
Tripura	21. Jan. 1972
Uttar Pradesh	24. Jan. 1950

Q 3. Which one of the following is not included in the state list in the Constitution of India?

निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है?

(a) Police

(b) Law and Order

(c) Prison

(d) Criminal Procedure Code

- Criminal law and criminal procedure fall under the Concurrent List while matters relating to Police and Prisons fall under the State List.
- The laws that govern criminal law in India are the Indian Penal Code, 1860 (IPC), and the Criminal Procedure Code, 1974 (CrPC).
- आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं जबकि पुलिस और जेल से संबंधित मामले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
- भारत में आपराधिक कानून को नियंत्रित करने वाले कानून भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी), और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1974 (सीआरपीसी) हैं।

Q 4. The Sarkaria Commission was set up in the year _____.

सरकारिया आयोग की स्थापना वर्ष _____ में की गई थी।

1983 → गठित

1987 → रिपोर्ट

(a) 1989

(b) 1983

(c) 2002

(d) 1965

- The Sarkaria Commission was set up in June 1983 to examine the relationship and balance of power between state and central governments and suggest changes within the framework of the Constitution.
- The commission submitted its report to the then prime minister Rajiv Gandhi on 27 October 1987.
- राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करने और संविधान के ढांचे के भीतर बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी।
- आयोग ने 27 अक्टूबर 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

Q.5 When did the President declare emergency, on the request of Ex-Prime Minister Indira Gandhi?

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की?

a) 25 June 1975

b) 20 October 1975

c) 22 October 1975

d) 22 December 1976

The emergency of 25 June 1975

- The Emergency had a 21-month long period from 1975 to 1977 during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi. Officially issued by President Fakhruddin Ali Ahmed under Article 352 of the Constitution. The main reason for the emergency was an internal disturbance in the country then. The Emergency was in effect from 25 June 1975 until its withdrawal on 21 March 1977.
- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1975 से 1977 तक 21 महीने की लंबी अवधि तक आपातकाल लगा रहा।
- संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किया गया।
- आपातकाल का मुख्य कारण उस समय देश में मौजूद आंतरिक अशांति थी।
- आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को वापस लिये जाने तक प्रभावी रहा।

Q.6 The Sarkaria Commission is related to which of the following?

सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

H/w

a) Centre State Relations

b) Banking Reforms

c) Election Reforms

d) Freedom of Press in India

Q.7 Which schedule of the Indian Constitution divides the legislative powers between the Union and states?

भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची विधायी शक्तियों को संघ और राज्यों के बीच विभाजित करती है?

a) 6th Schedule

b) 7th Schedule

c) 8th Schedule

d) 9th Schedule

Q.8 Constitution of India guarantees which of the following to the states of India?
भारत का संविधान भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है?

(a) Territorial Integrity

(b) Sovereignty

(c) Right to secede from Union

(d) None of the Above

Q.9 Which of the following Articles of the Constitution deal with the legislative relations between the Centre and the states?

संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है?

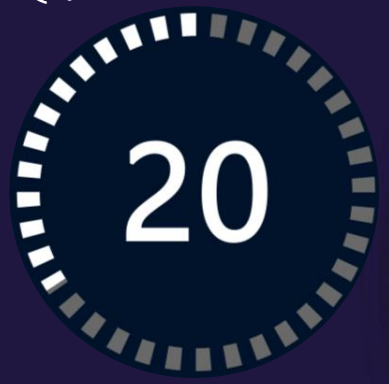

(a) Article 235 to 245

(b) Articles 245 to 255

(c) Article 255 to 265

(d) None of the above

- Articles 245 to 255 in Part XI of the Constitution of India deal with the legislative relations between the Centre and the states. Along with these there are some other articles dealing with the same subject.
- भारत के संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित हैं। इनके साथ-साथ इसी विषय पर कुछ अन्य लेख भी हैं।

Q.10 Which Prime Minister advised the President to proclaim emergency without consulting the cabinet?

किस प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति को कैबिनेट से परामर्श किए बिना आपातकाल घोषित करने की सलाह दी?

a) Jawaharlal Nehru
b) Gulzarilal Nanda
c) Indira Gandhi
d) Morarji Desai

Q.11 Who can make laws on any matter in the State List for implementing the international treaties, agreements or conventions?

अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून कौन बना सकता है?

a) The Parliament
b) The Council of Ministers
c) The Prime Minister
d) The Vice President

- The Parliament of India is empowered to make laws on any matter in the State List for implementing the international treaties, agreements or conventions. The provision enables the Central government to fulfill its international obligations and commitments.
- भारत की संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।